"हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ–226001

संख्या–461/सी0ई0ओ0–6–33/6–2013 लखनऊः दिनांकः मार्च, 2024

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

2–निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

जारी
24/03/2024

विषयः **स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता साक्षरता हेतु स्कूल/कॉलेजों में गठित Electoral Literacy clubs की वर्कशाप आयोजित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कर्यालय के पत्र संख्या–318/सीईओ–6, दिनांक 05.03.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता साक्षरता (Electoral Literacy) के लिए जनपद स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy clubs) की वर्कशाप दिनांक 11 से 18 मार्च, 2024 के मध्य नियत करते हुए निर्देशित किया गय था कि उक्त आयोजित वर्कशाप में मतदाता साक्षरता क्लब के सदस्यों शैक्षणिक संस्थाओं में नामित कैम्पस एम्बेसडर, नोडल अधिकारी तथा विधानसभा स्तर पर नामित Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व जनपद स्तर पर नामित स्वीप नोडल/सहायक नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिभाग करते हुए वर्कशाप आयोजित की जाय।

2– उपरोक्त आयोजित वर्कशाप हेतु जनपदवार अपने से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दिनांक 11 से 18 मार्च, 2024 की निर्धारित तिथियों का कैलेण्डर निम्न प्रारूप पर तैयार कर दिनांक 08.03.2024 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभीतक अप्राप्त हैः–

जनपद का नाम	वर्कशाप का दिनांक व समय	वर्कशाप का स्थान	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	प्रतिभाग करने वाले संबंधित कालेजों का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	वर्कशाप हेतु नोडल अधिकारी का नाम व नम्बर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अतः कृपया उपरोक्त सूचना बिना किसी विलम्ब के ई–मेल ceoupsection6@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

c:\users\hp\desktop\suhail-23-24\elc-2024\elc note-23-24.docx

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या– 620 /सत्तर–3–2024

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024**

विषयः प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में NISHE (National Initiative for Skill Integrated Higher Education) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण/कुलसचिवगण, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज किस्प संस्था एवं अन्य सभी सम्बन्धित के साथ दिनांक 14.03.2024 को गूगल मीट के माध्यम से सम्पन्न वर्चुअल बैठक के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रश्नगत AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) संचालित करने के लिए उपयुक्त उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन करते हुए चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची **प्रत्येक दशा में 03 दिन के भीतर शासन को ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–वर्चुअल बैठक दिनांक 14.03.2024 का कार्यवृत्त।

भवदीय,
/
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रो0 बलराज चौहान, स्टेट लीड, किस्प संस्था, लखनऊ/सुश्री निधि बिष्ट, किस्प–केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।
4– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
5– समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

Gmail संख्या 620 /सात्र-3-2024 H.E. Section-3 <hesection.3@gmail.com>

Fwd: Minutes of Meeting and Uttar Pradesh Presentation - March 14, 2024

Nidhi Bisht <nidhibisht15@gmail.com> Thu, Mar 21, 2024 at 3:32 PM
To: splsecretaryhe@gmail.com, hesection.3@gmail.com
Cc: tyagigk@nic.in, Subrahmanyam Reddi <admin@crispindia.net>, subba rao vedula <subba61@gmail.com>, balraj@crispindia.net, Nagesh Babu Adapureddy <nagesh@crispindia.net>

Respected Sir,

Warm greetings,

I hope this email finds you well.

As requested, please find attached the Hindi translation of the minutes of the meeting held with the UP Higher Education Department and Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) on 14th March 2024. I have thoroughly reviewed the document to ensure accuracy, but I apologize in advance for any mistranslation that may have occurred.

Additionally, I have included the CRISP Uttar Pradesh presentation and the English version of the minutes for your review.

Looking forward to hearing from you soon.

Thank you.

Warm regards,
Nidhi Bisht
CRISP-Central Office
9650771641
[Quoted text hidden]

3 attachments

NISHE_Meeting with Prl Secy, HE Dept, Govt of UP - 14.03.2024 (Hindi).pdf
309K

NISHE_Meeting with Prl Secy, HE Dept, Govt of UP - 14.03.2024.docx
212K

CRISP UP Presentation 14th March 2024.pdf
3160K

27/3/2024

CRISP
Deliberate. Design. Deliver.
Centre for Research in Schemes and Policies

14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें एप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स (एईडीपी) के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:

1. महेंद्र अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
2. राज्य के विश्वविद्यालयों के उपाध्यक्षों और रजिस्ट्रारों
3. आर. सुब्रह्मण्यम, सीईओ और सचिव, क्रिस्प (CRISP)
4. श्री सीताराम जे कुंटे, क्रिस्प मेंटर
5. आर. नागेश बाबू, क्रिस्प- केंद्रीय कार्यालय
6. निधि बिष्ट, क्रिस्प- केंद्रीय कार्यालय
7. राहुल अब्रोल, क्रिस्प यूपी टीम
8. दिव्या मलाकर, क्रिस्प यूपी टीम
9. आशुतोष सिंह, क्रिस्प यूपी टीम

आर. सुब्रह्मण्यम ने प्रमुख सचिव और अन्य शैक्षिक प्रमुखों का स्वागत किया, क्रिस्प यूपी टीम और क्रिस्प केंद्रीय कार्यालय टीम को मीटिंग के उपस्थितियों को परिचयित किया।

चर्चा बिंदु

1. आर. सुब्रह्मण्यम ने उत्तर प्रदेश को कौशल-एकीकृत उच्च शिक्षा के लिए कदम उठाने में पहले राज्यों में से एक बताया। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) और क्रिस्प (CRISP) के बीच एक एमोयू (MOU) साइन हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और शिक्षा पर परियोजना (PEHLE-UP) की शुरुआत हुई। इस परियोजना का एक प्रमुख ध्यान नौकरियों की ओर से कौशल-एकीकृत शिक्षा के माध्यम से है। उन्होंने यह भी बताया किया कि PEHLE-UP को मुख्य सचिव ने 6 जुलाई, 2023 को समीक्षा की गई, जिसमें एप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) के लिए 100 कॉलेजों का चयन, पाठ्यक्रम की तैयारी, और यूनिवर्सिटियों द्वारा इन पाठ्यक्रमों की मंजूरी के बारे में चर्चा शामिल थी।
2. श्री आर. सुब्रह्मण्यम ने इस एडीपी की आवश्यकता पर और भी जोर दिया, जो सामान्य शिक्षा को पेशेवर शिक्षा में परिवर्तित करती है, जिसमें अप्रेंटिसशिप इसके पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने इस

परियोजना में सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) और क्रिस्प की भूमिकाओं को भी उजागर किया। उन्होंने यह भी कहा कि ये कार्यक्रम NCF के साथ संरेखित हैं और 3 वर्षीय और 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के लिए एडीपी के लिए एक आधार मॉडल प्रोग्राम संरचना प्रस्तुत की गई।

3. क्रिस्प ने 11 अगस्त, 2023 को 119 कॉलेजों की सूची प्राप्त की, और 18 अगस्त, 2023 को, यूपी सरकार ने उन सभी चयनित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। 94 कॉलेजों को चुन लिया गया, और क्रिस्प ने इन कॉलेजों की मांगों और आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए उपाय किए, अनुरूप समायोजन किया। श्री आर. सुब्रह्मण्यम ने दिखाया कि लगातार और सहयोगात्मक प्रयासों के बावजूद, केवल 3 कॉलेज इन पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है। अब तक, केवल 23 कॉलेजों को मंजूरी मिली है, 18 की प्रतीक्षा में है, और बाकी 53 ने तो आवेदन भी नहीं किया है, या उनकी मंजूरियों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।
4. श्री आर. सुब्रह्मण्यम ने विश्वविद्यालय-वार कॉलेज मंजूरी आंकड़े प्रस्तुत किए, और इस सूची को मुख्य सचिव और वीसीओ (VCs) के लिए उनकी समीक्षा के लिए साझा किया गया। यूपी में चुनौतियों पर चर्चा की गई, और अनुमोदनों की देरी और परियोजना को अभी तक शुरू नहीं होने के कारणों पर चर्चा की गई। उन्होंने मुख्य सचिव से सलाह मांगी कि यूपी के लिए क्या योजना होनी चाहिए ताकि ये पाठ्यक्रम आने वाले शैक्षिक वर्ष 2024-25 में सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा सकें। क्रिस्प ने यूपी के 11 क्षेत्रों में 148 कॉलेजों को 8800 अप्रेंटिसशिप प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। ये आंकड़े यूपी में उद्योगों का विश्लेषण करने के बाद एसएससीओं द्वारा उद्धृत किए गए थे।
5. श्री आर. सुब्रह्मण्यम ने मुख्य सचिव के लिए तीन महत्वपूर्ण परिवेशनों पर जोर दिया:
   i. उन्होंने उन विश्वविद्यालयों के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता हासिल की, जिन्हें कम प्रेरणा दिखाई दे रही है; क्या वे परियोजना में बने रहें या पुनर्विचार किया जाए?
   ii. यह अत्यंत आवश्यक है कि मंजूरी पोर्टल (approval portal) की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए कॉलेजों को मंजूरियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए।
   iii. मंजूरी शुल्क (approval fees) संरचना के आसपास की अस्पष्टता को समझना और सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि पहल की स्पष्टता और समृद्धि सुनिश्चित हो।

6. श्री सीताराम कुंटे ने शिक्षा और कौशल के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने में एडीपी की महत्वता को जोर दिया।
   - उन्होंने विश्वविद्यालयों से इन पाठ्यक्रमों को त्वरित अनुमोदन देने और उनकी सूचना, जिसमें उनका क्रेडिट संरचना और पाठ्यक्रम शामिल है, को बेहतर समझ के लिए व्यापक रूप से प्रसारित करने की आग्रह किया।

- मॉडल पाठ्यक्रमों का विकसित किया गया है एसएससीओं द्वारा, और उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने के लिए संबंधित विभागों और शैक्षिक प्रमुखों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
- उन्होंने संबंधित विभागों और शैक्षिक प्रमुखों के साथ मॉडल पाठ्यक्रमों के आधार पर चर्चा की और उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का सुझाव दिया।
- 8800 छात्रों के लिए संभावित लाभों को हाइलाइट करते हुए, उन्होंने तत्काल कानूनी मंजूरी प्रक्रियाओं की आवश्यकता को बल दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण भूमिका है।

7. मुख्य सचिव की मुख्य अवलोकन:
   - केवल 23 कॉलेजों की मंजूरी का क्या कारण था, जिसमें केवल 3 ने पाठ्यक्रम की शुरुआत की?
   - पाठ्यक्रम में प्रवेश में यद्यपि कमी दिखाई दी जा रही है, इसका कारण क्या है?
   - 53 कॉलेजों से आवेदन की अनुपस्थिति का कारण देरी व मंजूरियों की अवधि के दौरान पोर्टल का बंद होना हो सकता है।
   - एसएससी अनुबंध शुल्क (affliation fees) के चारों ओर संदेह को उच्च प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की आवश्यकता है।
   - मुख्य सचिव ने 2024-25 शैक्षिक वर्ष के लिए 250-300 कॉलेजों की पहचान का कार्य समाप्त मार्च 2024 के अंत तक भराया, चयन मानदंड का विवरण:
     1. प्रमुखता, प्रसिद्ध संस्थान, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, और राज्य के स्वायत्त कॉलेज।
     2. प्रचुर संसाधनों और बड़े छात्र जनसंख्या को समाहित करने की क्षमता वाले कॉलेज।
     3. उन संस्थानों का उत्साह जो इन पाठ्यक्रमों की प्रस्ताविता में भाग लेने के लिए तत्पर हैं।
     4. यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित हों, जिसमें अभ्यासीपन निकट सैद्धांतिक शिक्षा के लिए उपलब्ध हो।

   - उन्होंने पूछा कि इन पाठ्यक्रमों के शब्दावली (nomenclature) को क्या बदला जा सकता है, उदाहरण के लिए, बीबीए को?
   - उन्होंने यह अनुरोध किया कि सरकारी कॉलेजों को इन अनुबंध शुल्कों से मुक्त किया जाए या शुल्क को न्यूनतम रखा जाए, क्योंकि सरकारी कॉलेज नए कोर्स शुरू करने के लिए बहुत ही कमोत्तेजित हैं, यह उन्हें इन एडीपीडीएस प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने एसएससीओं से अनुबंध शुल्क को प्रति व्यक्ति लेने और सभी एसएससीओं के शुल्क संरचना के समानता को बनाए रखने का अनुरोध किया।
   - उन्होंने एक जिला-एक उत्पाद (ओडी-ओपी) कोर्सों का एक अनुरोध किया था जो एसएससी से कुछ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है जो पहले से चल रहे सामान्य डिग्री के पाठ्यक्रमों

में डाले जा सकते हैं। ये कोर्स न केवल मंजूरी प्राप्त करने में सरल होंगे बल्कि बड़े जनसंख्या की भी सेवा करेंगे।

8. श्री आर. सुब्रह्मण्यम ने स्पष्ट किया कि:
    - मंजूरी प्राप्त होने पर प्रवेश बंद कर दिया गया था, जिससे 20 कॉलेज को पाठ्यक्रम आरंभ करने में असमर्थ हो गए, उनकी प्राथमिकता इस वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए उनकी आरंभ करने में रखी गई।
    - उन्होंने शब्दावली की समस्याओं को स्वीकार किया और सीआरआईएसपी के प्रयासों को स्वीकृति दी जो बीए / बीएससी / बीकॉम जैसे डिग्री कार्यक्रमों का नामकरण करने की दिशा में काम कर रहा है।
    - उन्होंने वादा किया कि सीआरआईएसपी एसएससीओं के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा ताकि संबंधन शुल्क संरचना पर काम किया जा सके, यदि आवश्यक हो तो उन्हें कम किया जाए या सीआरआईएसपी द्वारा प्रबंधित किया जाए।
    - उन्होंने शुल्क प्रबंधन में पारदर्शिता की गारंटी दी, अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा और पाठ्यक्रम की कीमतीता को बढ़ाने के लिए छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव दिया।
    - साथ ही, उन्होंने प्रशिक्षुता को विशिष्ट स्थापित उद्योगों में स्थानांतरण की ज्यादा चर्चा की।

9. जाननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय (जेएनसीयू) बलिया के उपाध्यक्ष ने पहल की और मंजूरियों को देरी को स्वीकार किया जिसकी वजह से इन पाठ्यक्रमों की देर से प्रारंभ हो गई, लेकिन इन्हें जेएनसीयू में इस शैक्षिक वर्ष से कार्यान्वित करने के लिए, उन्होंने सीआरआईएसपी से करिक्युलम शेयर करने की अनुमति मांगी ताकि वह इसे मार्च के बाद प्रस्तुत करके शुरू कर सकें।

10. विवेक कुमार, NATS कानपुर, ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए:
    - उनके मूल्यांकन के अनुसार, यूपी एक औद्योगिक राज्य नहीं है, और 37 जिले उद्योगों के बिना अंदर किए गए हैं। यदि अप्रेंटिसशिप को प्रस्तुत किया जाए, तो छात्रों को पुनः बसेरा की समस्या उत्पन्न होती है और जो उन्हें इन पाठ्यक्रमों को चुनने से निराश करता है। इन पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों को पहचाना जाना चाहिए, जिसके चारों ओर कॉलेज की पहचान की जानी चाहिए।
    - ये पाठ्यक्रम स्थानीय अप्रेंटिसशिप प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, जो इन पाठ्यक्रमों की स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - यह सुझाव दिया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शुल्क होते हैं, स्थानीय उद्योगों को अपने सीएसआर निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इन पहचानित कॉलेजों को या छात्रों के शुल्क को वित्त प्रदान किया जा सके, जो उद्योग इन छात्रों को भर्ती करने में प्रोत्साहित कर सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही इनमें निवेश किया है।

- इन AEDPs के प्रचार में स्थानीय भाषा में बहुत महत्व है, कॉलेज और छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषा में इन पाठ्यक्रमों के बारे में वीडियो बनाने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाना चाहिए।

क्रियान्य बिंदु

- मार्च 2024 के अंत तक, राज्य सरकार को कॉलेजों की पहचान करनी चाहिए। कॉलेजों की पहचान मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की जानी चाहिए, "मात्रा के बजाय गुणवत्ता"।
- क्रिस्प को 31 मार्च 2024 तक यूनिवर्सिटी को पाठ्यक्रम प्रेषित करने की अनुमति है, ताकि VC जल्द ही इन पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे सकें।
- कॉलेजों की पहचान के बाद, कॉलेजों को इन पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध संसाधनों और शिक्षकों की जांच करनी चाहिए, जिसका शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का लागत जिम्मेदारी क्रिस्प ने ली है।
- मई 2024 में जानकारी, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियाँ शुरू की जानी चाहिए। स्थानीय भाषा में एक अपरेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम प्रमोशन वीडियो बनाया जा सकता है, और यह जून में शुरू किया जाएगा ताकि पाठ्यक्रम जुलाई 2024 में आरंभ किया जा सके।
- मुख्य सचिव और VC से अनुरोध किया जाता है कि इन पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाए और सफल कार्यान्वियन के लिए साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

समापन

समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, श्री आर. सुब्रह्मण्यम और श्री सीताराम कुंटे, मुख्य सचिव और वीसी को धन्यवाद देते हुए, उत्तर प्रदेश में आगामी शैक्षिक वर्ष 2024-25 में एडपी को कार्यान्वित करने का निश्चय किया। समापन में सभी सदस्यों ने निर्धारित समयसारिणी का पालन करने का सहमति जताई।

***

Timeline

S.No.	Activity	Completion Date	To be done by
1	Meeting with the State Government	15.03.2024	CRISP & State Govt.
2	Communication of Selected Colleges & AEDPs to CRISP	31.03.2024	State Govt.
3	Curriculum submission to Universities for BoS approval	01.04.2024	SSCs and CRISP
4	SSCs signing individual MoUs with Affiliating Universities or Autonomous Colleges	15.04.2024	State Govt., SSCs & Colleges
5	Approval by Universities BoS and Academic Council to selected colleges	30.04.2024	State Govt./ Universities
6	Communicating the identified Faculty for Training	15.05.2024	Colleges
7	Faculty Training	31.05.2024	SSCs/ CRISP
8	Classrooms & Labs Preparation	15.06.2024	Colleges
9	Preparation of Admissions Portal	01.07.2024	State Govt.
10	Starting of Classes	01.08.2024	Colleges

***

CRISP
Deliberate. Design. Deliver.
Centre for Research in Schemes and Policies

A virtual meeting was held with the Government of Uttar Pradesh on 14th March to discuss on the implementation of Apprenticeship Embedded Degree Programs (AEDPs) from AY 2024-25 on a large scale in Uttar Pradesh. The following officials took part in the meeting:

1. Mr. Mahendra Agarwal, Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh
2. Vice Chancellors & Registrars of State Conventional Universities
3. Mr. R. Subrahmanyam, CEO & Secretary, CRISP
4. Mr. Sitaram J Kunte, CRISP Mentor
5. Mr. A. R. Nagesh Babu, CRISP Central Office
6. Ms. Nidhi Bisht, CRISP Central Office
7. Mr. Rahul Abrol, CRISP UP Team
8. Ms. Divya Malakar, CRISP UP Team
9. Mr. Ashutosh Singh, CRISP UP Team

Mr. R. Subrahmanyam welcomed the Principal Secretary and other academic heads to the meeting, introducing the CRISP UP team and CRISP central office team to the attendees.

Discussion Points

1. Mr. R. Subrahmanyam talked about Uttar Pradesh being one of the first states to initiate steps for skill-integrated higher education. An MoU was signed between the Uttar Pradesh Government (GoUP) and CRISP, initiating the Project for Excellence in Higher Learning & Education in UP (PEHLE-UP) on January 25, 2023. One of the key focuses of this project is on job orientation through skill-integrated education. He also mentioned that the PEHLE-UP project was reviewed by the Chief Secretary on July 6, 2023, which included discussions like the selection of 100 colleges for the Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs), preparation of curriculum, and approvals for these courses by universities.
2. Mr. R. Subrahmanyam further emphasized the need for these AEDPs, which transform general education into professional education, with apprenticeship being an integral part of

its curriculum. He also highlighted the roles of Sector Skill Councils (SSCs) and CRISP in this project. He also stated that these programs are NCF aligned and presented a base model program structure for AEDPs for 3-year and 4-year degree programs.

3. CRISP received the list of 119 colleges on August 11, 2023, and on August 18, 2023, the GoUP conducted a workshop with all the selected colleges and universities. 94 colleges were narrowed down, and CRISP addressed the demands and needs of these colleges, making adjustments accordingly. Mr. R. Subrahmanyam showcased that despite the continuous and collaborative efforts, only 3 colleges have started these courses. So far, only 23 colleges received approvals, 18 are pending, and the rest 53 have not even applied, or there is no clarity regarding their approvals, their response has been lukewarm.
4. University-wise college approval statistics were showcased by Mr. R. Subrahmanyam, and this list has also been shared with the Principal Secretary and the VCs for their perusal. Challenges were discussed in UP, and reasons were discussed on why approvals are delayed and why the project hasn't taken off yet. He sought the Principal Secretary's advice on what should be the strategy for UP so these courses can be launched successfully in the upcoming Academic Year 2024-25. CRISP has proposed 148 colleges providing 8800 apprenticeships in 11 sectors across UP. These numbers were quoted by the SSCs upon analysing the industries in UP.
5. Mr. R. Subrahmanyam highlighted three crucial considerations for the Principal Secretary:
    i. A decision needs to be made regarding the universities exhibiting low motivation; should they remain within the project or be reconsidered?
    ii. It is imperative to maintain the availability of the approval portal, extending the deadline for colleges to submit their applications for approvals.
    iii. Addressing the ambiguity surrounding the approval fees structures is essential for ensuring clarity and smooth progression of the initiative.
6. Mr. Sitaram Kunte emphasized the significance of AEDPs in addressing the unemployment through education and skilling.
    - He urged universities to approve these courses promptly and ensure that information about them, including their credit structure and curriculum, is widely disseminated for better understanding.
    - Model curriculums have been developed by SSCs, and discussions should be held with relevant departments and academic heads to tailor them according to specific needs.

- He suggested considering adjustments to affiliation fees to incentivize colleges to offer AEDPs.
- Highlighting the potential benefits for 8800 students, he emphasized the need for swift legal approval processes, with universities playing a crucial role in this regard.

7. Principal Secretary's Key Observations:
   - What factors led to the approval of only 23 colleges, with merely 3 initiating the course?
   - Why is there a notable decrease in course admissions?
   - The absence of applications from 53 colleges may be attributed to late approvals and the portal closure during their application period.
   - Ambiguity surrounding SSC affiliation fees needs resolution at a higher administrative level.
   - The Principal Secretary entrusted the task of identifying 250-300 colleges for the academic year 2024-25 by the end of March 2024, specifying selection criteria:
     i. Colleges of significance, renowned institutions, government-funded establishments, and autonomous colleges within the state.
     ii. Colleges with substantial resources and capacity to accommodate a large student population.
     iii. Institutions demonstrating eagerness to participate in offering these courses.
     iv. Ensuring courses are tailored to local needs, with apprenticeships available within nearby industries for practical training.
   - He enquired whether the terminology of these courses, for example, BBA, could be changed.
   - He requested that government colleges should be exempted from these affiliation fees or fees should be minimal as the government colleges are already very low on motivation to start new courses, this would encourage them to initiate these AEDPs. Also requested the SSCs to charge the affiliation fees per head and have a uniformity regarding the fee structure across all SSCs.
   - One District-One Product (OD-OP) courses have been requested from the SSC to provide some certification courses which can be put into already running general degree courses. These courses will not only be easier to get approved but also cater to the larger mass.

8. Mr. R. Subrahmanyam clarified that:
   - Admissions were closed when colleges received approvals, resulting in 20 colleges unable to commence the courses, prioritizing their initiation for the current academic year.
   - He acknowledged terminology issues and affirmed CRISP's efforts to rename degree programs like BA/BSc/BCom.
   - He assured that CRISP would leverage its influence with SSCs to address the affiliation fee structure, ensuring they are minimized or managed by CRISP, if necessary.
   - He guaranteed transparency in fee management, ruling out overcharging, and proposed scholarships to enhance course affordability.
   - Additionally, he highlighted the placement of apprenticeships in well-established industries with favourable reputation.
9. Vice Chancellor, Jananayak Chandrashekhar University, (JNCU) Ballia, took the initiative and acknowledged the delayed approvals due to which the late commencement of these courses but to implement them in JNCU from this academic year, he requested CRISP to share the curriculum with the university so he can get it approved and start the process after March.
10. Vivek Kumar, NATS Kanpur, made some key observations:
    - According to their assessment, UP is not an industrial state, and 37 districts have been identified without industries. If apprenticeships are to be introduced, the issue of student relocation arises and which discourages students to opt for these courses. To introduce these courses, industry clusters should be identified around which the colleges should be identified.
    - These courses should be able to provide local apprenticeships, focused on the localization of these courses.
    - Suggested that since professional courses have high fees, local industries should be encouraged to use their CSR funds to fund these identified colleges or fees of the students, which might give the industry an incentive to hire these students as they have already invested in them.
    - Promotions of these AEDPs in the local language are important, colleges and students need to be oriented about these courses through videos about these AEDPs in the local language, and social media should also be used to promote these courses.

Action Points

- By the end of March 2024, the state government should identify the colleges. The colleges should be identified based on the criteria set by the Principal Secretary, "quality over quantity".
- CRISP may send the curricula to the universities by March 31, 2024, so that VCs can get these courses approved soon.
- After the identification of the colleges, colleges need to check the facilities and faculty available for these courses, the responsibility of the cost training for these faculty has been taken up by CRISP.
- Information, Education, and Communication (IEC) activities need to be started by May 2024. An AEDP promotion video may be made in the local language, and this will be started in June so that the courses can commence in July 2024.
- Principal Secretary and VCs are requested to make the implementation of these courses a priority and have weekly reviews for successful implementation.

Adjournments

The meeting adjourned with Mr. R. Subrahmanyam and Mr. Sitaram Kunte expressing their gratitude to the Principal Secretary and the VCs, resolving to implement AEDPs in UP in the upcoming academic year 2024-25. The meeting concluded with all members agreeing to adhere to the agreed timeline.

***

Timeline

S.No.	Activity	Completion Date	To be done by
1	Meeting with the State Government	15.03.2024	CRISP & State Govt.
2	Communication of Selected Colleges & AEDPs to CRISP	31.03.2024	State Govt.
3	Curriculum submission to Universities for BoS approval	01.04.2024	SSCs and CRISP
4	SSCs signing individual MoUs with Affiliating Universities or Autonomous Colleges	15.04.2024	State Govt., SSCs & Colleges
5	Approval by Universities BoS and Academic Council to selected colleges	30.04.2024	State Govt./ Universities
6	Communicating the identified Faculty for Training	15.05.2024	Colleges
7	Faculty Training	31.05.2024	SSCs/ CRISP
8	Classrooms & Labs Preparation	15.06.2024	Colleges
9	Preparation of Admissions Portal	01.07.2024	State Govt.
10	Starting of Classes	01.08.2024	Colleges

***